ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.-228-229**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

उच्च शिक्षा की गुणात्मकता में चुनौतियाँ

डॉ0 राम लखन पाण्डेय

असिस्टेंट प्रोफेसर– शिक्षाशास्त्र विभाग, के0बी0पी0जी0 कालेज, मीरजापुर (उ0प्र0) भारत

Received-14.08.2024, Revised-21.08.2024, Accepted-28.08.2024 **E-mail : ramlakhan4094@gmail.com**

सारांशः ***प्रत्येक देश में उच्च शिक्षा को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है क्योंकि उच्चकोटि के, नेता, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इन्जीनियर, साहित्यकार, दार्शनिक, विश्वविद्यालय के प्रांगण से ही उत्पन्न होते हैं। उच्चकोटि के सत्यान्वेषण के लिए विश्वविद्यालय ही उत्तम प्रयोगशालायें हैं। इंग्लैण्ड, अमेरिका, रूस, तथा अन्य देशों में प्राथमिक शिक्षा को शिक्षा की आधारशिला के रूप में और उच्च शिक्षा को मुकुट और ताज के रूप में स्वीकार किया गया है। उच्च शिक्षा का यही स्थान भारत में भी है। भारत में प्राचीन काल से ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती रही है। वैदिक काल में गुरूकुल व आश्रम तथा बौद्धकाल में मठ व विहार उच्च शिक्षा के केन्द्र थे। बौद्ध व गुप्त काल में नालन्दा, तक्षशिला व विक्रमशिला विश्वविद्यालय सुविख्यात थे, यहाँ विश्व भर से लोग अध्ययन करने के लिए आते थे। मध्यकाल में मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी।***

कुंजीभूत शब्द– उच्च शिक्षा, आधुनिकीकरण, संस्कृति, शिक्षा की चुनौती, अनुसंधान, गुणात्मक विकास, सार्थक उद्देश्य

भारत में प्राचीन काल से ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती रही है। वैदिक काल में गुरूकुल व आश्रम तथा बौद्धकाल में मठ व विहार उच्च शिक्षा के केन्द्र थे। आधुनिक काल में उच्च शिक्षा की की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार की देन है जिसका हमारी भारतीय संस्कृति से कोई सम्बन्ध नहीं है। 'शिक्षा की चुनौती' नामक दस्तावेज में लिखा गया है कि "व्यापक रूप से विश्वास किया जाता है कि किसी देश की उच्च शिक्षा की स्थिति को ही उसके भविष्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेत कहा जा सकता है। भारत के पूर्व प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरू, जिन्होंनें भारत के आधुनिकीकरण की नींव डाली थी, वह घोषणा की थी कि यदि विश्वविद्यालय ठीक होगें तो राष्ट्र भी ठीक होगा, लेकिन इसके बावजूद कि उच्च शिक्षा को मुख्य भूमिका प्रदान की गई, इस क्षेत्र में बहुत कम प्रगति हुई। हालांकि विश्वविद्यालय के कुछ कालेजों तथा संकायों नें अनुसंधान कार्य करकें और विद्वान पुरुषों तथा महिलाओं की सहायता से उक्त विकास एवं आधुनिकीकरण की प्रकिया को समर्थन देने में निर्णायक भूमिका निभाई है, फिर भी विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों की सामान्य क स्थिति राष्ट्र के लिए भारी चिन्ता का विषय है।"

भारत में उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में अनेक चुनौती उत्पन्न हो रही है –

उद्देश्यहीनता : आज उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्याथियों के सामने कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थी किसी प्रकार से उपाधि प्राप्त करना चाहता है, चाहे उसे बुरे उपाय का ही सहारा ही क्यों न लेना पड़े। उच्च शिक्षा के अभिष्ट उद्देश्य के बारे में मतैक्य का अभाव है। जब उच्च शिक्षा का उद्देश्य ही ठीक नहीं होगा तब शिक्षा व्यवस्था के ठीक बने रहने का आशा करना ही अनुचित है आज की उच्च शिक्षा से अनेक अयोग्य, परावलम्बी नागरिक तैयार हो रहे है तथा उच्च शिक्षा पर होने वाला व्यय अपव्यय हो रहा है।

उच्च शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को व्यावहरिक जीवन के लिए तैयार किया जाना चाहिये, केवल नौकरी के लिए नहीं। हमारी सामाजिक संरचना परिर्वतनशील है अतः उच्च शिक्षा के प्राचीन उद्देश्यों में परिर्वतन किया जाए जिससे राष्ट् की प्रगति सुनिश्चित हो सके तथा हतास, कुंठित, बेरोजगारों की संख्या कम हो सके। न्यूमैन ने कहा है कि–" यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का कोई व्यावहरिक उद्देश्य है तो मैं कह सकता हूँ कि यह समाज में उत्तम .. नागरिकों को प्रशिक्षित करता है।" विश्वविद्यालयों का कर्तव्य है कि वे ज्ञान की सीमाओं को विस्तीर्ण करें और ऐसे विद्वान तथा साहसी छात्रो को उत्पन्न करे जो देश की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ समस्त क्षेत्र में नेतृत्वग्रहण करने की क्षमता रखतें हों। इस दृष्टि से राधाकृष्णन आयोग तथा कोठारी आयोग द्वारा निर्धारित उच्च शिक्षा के उद्देश्यों पर ध्यान देना अतिआवश्यक है।

पाठ्यक्रम की समस्या : उच्च शिक्षा का पाठ्यकम देश की वर्तमान एवं भावी आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, संकीर्णता के दोष से पीड़ित है। कहीं छात्रों को रूचिकर विषय नहीं मिल पाते तो कहीं उन्हें ऐसे पाठ्यकम मिलता है जो

व्यक्ति व समाज के लिए अनुपयोगी, कठोर, अपर्याप्त, अस्पष्ट कम विविधता वाला तथा परीक्षा केन्द्रित होता है इसमें प्रायःअन्तरवैषयिकज्ञान पर बल नहीं दिया जाता तथा व्यावसायिक विषयों का इसमें अभाव है।

कोठारी आयोग ने स्नातक–पूर्व स्नातकोत्तर स्तर पर अधिक लचीली पाठ्यचर्या बनाने, छात्रों को अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक पाठ्यवस्तु चुनने की सुविधा देने, छात्र सेवाओं को शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप् में संगठित करनें आदि सुझाव दिये। यू० जी० सी० ने 1976 में ग्रामीण समुदाय की विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या, कार्य क्षेत्र एवं अधिगम क्षेत्र में समन्वय तथा नए पाठ्यचर्या हेतु महत्वपूर्ण दिये। यू० जी० सी० के 2003 के सुझाव, कि पाठ्यचर्यात्मक प्रतिमान अर्थात वार्षिक, सेमेस्टर या ट्राइमेस्टर प्रणाली के आधार पर प्रथम उपाधि के कार्यकम को पूरी अवधि में समान रूप से फैलायें जाय, विश्वविद्यालय को कैफीटोरिया उपागम का प्रयोग किया जाय जिससे छात्र आवश्यकतानुसार कार्यों की वांछित संख्या चुन सके, पाठ्यचर्या के क्रियांवयन का ढंग जैसे व्याख्यान, ट्युटोरियल, प्रयोगशाला सत्र, गोष्ठी, क्षेत्र–कार्य, प्रजेक्ट कार्य आदि निश्चित किए जाय, पाठ्यचर्या में उनके लिए निर्धारित क्रेडिट भी दिये जाय, पाठ्यचर्या के कुछ अंश स्वयं पढ़ने के लिए प्रोत्सहित किया जाय जिससे पुस्तकालय, प्रयोगशाला, इण्टरनेट आदि का भरपूर प्रयोग किया जा सके आदि को स्वीकार कर पाठ्यचर्या को प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

शिक्षा के माध्यम की चुनौती : उच्च शिक्षा के माध्यम के बारे मे विद्वानो में मतैक्य नहीं है अनेक महाविद्यालयों व विश्वविद्यालय विभागों में शिक्षा का माध्यम आज भी अग्रेजी भाषा है। अधिकांश छात्रों को अग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने एवं विचार व्यक्त करनें में कठिनाई होती है। समय, परिश्रम, शक्ति, रटनें की प्रवृत्ति का दुरूपयोग होता है। इससे एक ओर कल्पना शक्ति व स्मरण योग्यता घटती है तो दूसरी ओर अधिक छात्र परीक्षा में असफल हो जाते है फलस्वरूप उनका व्यक्तित्व दबनें लगता है कुछ महाविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती है परन्तु इन छात्रों के समने अद्यतन जानकारी प्राप्त करनें तथा स्तरीय पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धत न होने की जटिल समस्या मौजूद है।

कोठारी आयोग के अनुसार पूर्व–स्नातक स्तर पर उच्च शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए तथा स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा का माध्यम आज अंग्रेजी भाषा रहना चाहिए के० आर० वी० राव के अनुसार पूरे देश के विश्वद्यिालयों को अपनी–अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वोत्तम पुस्तकों का अनुवाद करनें के लिए प्रोत्सहित करना चाहिए। अनुवाद कार्य करनें के लिए यू० जी० सी० को पुस्तक अनुदान' देना चाहिए स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय राष्ट्र भाषा होनी चाहिए परन्तु सभी परिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी रूपान्तर अवश्य बतानें चाहिए।

परीक्षा प्रणाली की चुनौती : आज परीक्षा प्रणाली अत्यधिक दूषित हो गयी है। नकल करने व कराने में धन व्यय हो रहे है। छात्रों को नकल करनें के लिए प्रोत्साहन उन्हीं से मिलता है जिन्हें परीक्षा के सही संचालन का दायित्व दिया जाता है। परीक्षा प्रणाली में अनेक स्तरों पर धाँधली होती है। पर्चे आउट करानें, नकल करानें, मूल्यांकन में पक्षपात, टेबुलेशन में गड़बड़ी, परीक्षा के संचालन में अनियमितता, परीक्षाकों के नियुक्ति में धाँधली, परीक्षाओं का बहिस्कार, बोनस अंक देनें की परम्परा, अनुपयुक्त प्रश्न–पत्र, दोषपूर्ण मूल्यांकन आदि उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।

राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठरी आयोग, नयी शिक्षा नीति आदि नें परीक्षा सुधार हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया गया था जो स्वीकार करनें योग्य है। यू० जी० सी० नें दिशा–निर्देश दिया कि प्रत्येक कोर्स में लिखित या मौखिक अथवा दोनो प्रकार की परीक्षा की प्रकृति बनायी जाय, दाइमेस्टर/सेमेस्टर /वर्षान्त परीक्षाओं के अतिरिक्त प्रत्येक कोर्स में सतत् सत्रीय मूल्यांकन किया जाय, क्षेत्र कार्य या प्रोजेक्ट कार्य को कार्स का अभिन्न अंग बनाया जाय, प्रश्नपत्रों का निमार्ण इस प्रकार से किया जाय कि उसकी व्याप्ति सम्पूर्ण कोर्स पर हो, मूल्यांकन का उद्देश्य अववोध तथा बिखरे सूचना तत्वों को संश्लेषित कर अर्थपूर्ण समष्टि की रचना करने की योग्यता का मूल्यांकन होना चाहिए, साथ ही विश्लेषणात्मक एवं मौलिक चिन्तन का उपयोग किया जाय, मूल्यांकन प्रकिया को पारदर्शी बनाया जाय आदि। यू० जी० सी० के ये दिशा–निर्देश स्वीकार करने योग्य है।

निम्न स्तरीय शिक्षण की चुनौती : हमारी उच्च शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है, फलस्वरूप यह शिक्षा मूल्यविहीन व निरर्थक होती जा रही है, सुयोग्य सहित्यकार, बैज्ञानिक, प्रबंधक, चिंतक, समाज व राष्ट्र सेवक आदि का अभाव होता जा रहा है। शिक्षक पूराने व्याख्यान या नोट लिखवानें तक सीमित है। वे शिक्षण विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना निरर्थक मानते है। अनेक अयोग्य शिक्षक उच्च शिक्षा के वातावरण को दूषित कर रहे है, तथा जो योग्य है उनके लिए अध्ययन व शोध कार्य हेतु पर्याप्त सुविधा का अभाव है। केन्द्र व राज्य विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सेवादशा में भिन्नता है जिससे शिक्षक अपने को संतुष्ट करनें के लिए अपने शिक्षण की गुणवत्ता का बलिदान कर देता है।

निष्कर्ष : उच्च शिक्षा की गुणात्मक वृद्धि हेतु शिक्षक के शिक्षण कौशल का विकास होना आवश्यक है इसके लिए सतत् शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। कार्यशाला, सेमिनार, अभिविन्यास कार्यकम की व्यवस्था किया जाय । नई शिक्षा नीति के सुझाव पर 51 ए.एस.सी. खोले गए, जो उच्च शिक्षा के शिक्षकों हेतु ओरियेटेशन, रिफ्रेशर, शार्ट टर्म कोर्स चला हरें हैं। शिक्षकों के लिए अध्ययन व शोध कार्य हेतु पर्याप्त सुविधा की वयवस्था होनी चहिए। केन्द्र व राज्य विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सेवादशा में समानता होनी चाहिए जिससे शिक्षक अपने को संतुष्ट कर अपने शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ा सके।

अन्ततः कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा की गुणात्मक वृद्धि के रास्ते में अनेक चुनौतियाँ है उनका समाधान तभी होगा जब केन्द्र व राज्य सरकार तथा स्वयं शिक्षक, उच्च शिक्षा की गुणात्मक वृद्धि हेतु जागरूक होगा।.

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. त्यागी, गुरशरनदास, भारतीय शिक्षा का परिदृश्य, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 2, पृष्ठ सं.–316–349.
2. पाण्डेय, रामशकल, भारतीय शिक्षा की सम–सामयिक समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स पृष्ठ सं.–162–198.
3. पाठक,पी० डी०, भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, श्री विनोद पुस्तक पुस्तक मन्दिर, आगरा 2, पृष्ठ सं. –337–3691.
4. सारस्वत मालती, भारतीय शिक्षा विकस एवं समस्याएँ, कैलाशा प्रकाशन इलाहाबाद पृष्ठ सं.–76–121.

*****